



सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों, और एक मूर्ख इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए।

मूल्य ₹ 3/-

-चाणक्य

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube 4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 12 ● अंक: 208 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 5 सितम्बर, 2026

यूएस ओपन में हारी सेरेना-विनस विलियस... 7 यूपी विस-27 चुनाव पर बिछने... 3 बंद स्कूल खुलेगा तो पीडीए... 2

मोदी सरकार की मुश्किलों का सीजन?

शाहीन प्रकरण से छात्र आंदोलन तक सवालियों की बारात सवाल सरकार से जवाब दे रही पुलिस

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली इस वक्त सिर्फ देश की राजधानी नहीं है दिल्ली इस वक्त सवालियों का ऐसा चौराहा बन चुकी है जहां हर रास्ता एक ही सवाल पर जाकर ठहर रहा है और पूछ रहा है कि आखिरकार मोदी सरकार से कहाँ गलतियाँ हो रही है? छात्र आंदोलन के बाद से लगता है कि मोदी सरकार का मुश्किलों का सीजन शुरू हो गया है। विपक्ष चैन से जीने नहीं दे रहा और बीजेपी की आंतरिक राजनीति सुकून से बैठने नहीं दे रही। वहीं विदेश नीति पर उठते सवाल और ईरान अमेरिका युद्ध से उपजी स्थितियाँ कोढ़ में खाज बनती दिखाई दे रही है।

एक तरफ कैमरा लेकर सत्ता से सवाल पूछने वाली दो महिला पत्रकारों का मामला है। दूसरी तरफ अपने भविष्य परीक्षा और रोजगार को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र हैं। एक तरफ पुलिस का दावा है कि आंदोलन में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल थे दूसरी तरफ उसी पुलिस के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम पर ऐसे सवाल उठ गए कि जिन लोगों को कैमरे ने प्रदर्शन स्थल पर मौजूद बताया उनमें से कम से कम 25 लोग उस वक्त जेल में थे। और फिर निशू आजाद के पिता पर हमले का मामला है जिसमें आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर राजनीतिक संरक्षण के आरोप उठे। अब सवाल यह नहीं है कि सरकार के खिलाफ कौन नारा लगा रहा है। सवाल यह है कि बार बार ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं जिनमें सरकार और जनता के बीच संवाद की जगह पुलिस हिरासत एफआईआर और कानून व्यवस्था का नैरेटिव खड़ा दिखाई देने लगता है।



जनता सरकार की साझेदार है या संदिग्ध?

शाहीन का कैमरा पूछ रहा है छात्रों की भीड़ पूछ रही है। निशू आजाद का परिवार पूछ रहा है। अदालत पूछ रही है। मीडिया पूछ रहा है और जनता पूछ रही है? कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला नागरिक सरकार का साझेदार है या संदिग्ध? यही वह सवाल है जिसका जवाब सिर्फ प्रेस कन्फ्रेंस से नहीं मिलेगा। इसका जवाब कार्रवाई से मिलेगा निष्पक्ष जांच से मिलेगा दोषी पर कार्रवाई से मिलेगा निर्दोष को राहत से मिलेगा और सबसे बढ़कर उस भरोसे से मिलेगा कि सत्ता चाहे जितनी ताकतवर हो सवाल उससे बड़ा है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि सरकारें विपक्ष से नहीं जनता के भरोसे के टूटने से कमजोर होती हैं। और अगर मोदी सरकार को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत जनता का भरोसा बचाए रखना है तो उसे आज सबसे पहले अपने आसपास उठ रही इन आवाजों को सुनना होगा। क्योंकि सवाल दबाए जा सकते हैं लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। और जब सवाल एक पत्रकार के कैमरे से निकलकर छात्र के हाथ में छात्र के हाथ से अदालत में और अदालत से पूरे देश की बहस में पहुंच जाए तब उसे विरोध नहीं लोकतंत्र का अलंकार समझना चाहिए।



शाहीन-नफीसा प्रकरण ने उठाये सवाल

शाहीन खान और नफीसा खान का मामला इसी सवाल को सबसे खतरनाक ढंग से सामने लाता है। 4PM से जुड़ी दो महिला पत्रकारों को रिपोर्टिंग स्थल से पुलिस वैन में बिठाकर साकेत पुलिस स्टेशन जबरदस्ती ले जाया गया और वहां उनके साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गयी। यही नहीं दोनों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मुस्लिम पहचान सामने आने के बाद कथित दुर्व्यवहार और बढ़ गया। नीट और दूसरी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने देशभर में छात्र



प्रदर्शनकारियों से जुड़ी एफआईआर खत्म कर दी जबकि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोगों के संबंध में पुलिस को आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसके बाद पुलिस के

उस दावे की पड़ताल सामने आई जिसमें दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों को आपराधिक रिकॉर्ड से जोड़ा गया था। इंडियन

एक्सप्रेस की जांच में कम से कम 25 ऐसे लोगों की पहचान सामने आई जो पुलिस के सिस्टम में प्रदर्शन स्थल पर दिखाई दिए लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय जेल में थे अब जरा ठहरिए। अगर किसी इंसान को कैमरा ऐसी जगह मौजूद बता दे जहां वह था ही नहीं तो सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है। सवाल उस तकनीक के आधार पर बनने वाले सरकारी नैरेटिव का है। क्योंकि कैमरा गलती करे तो गलती तकनीक की है। लेकिन अगर उस गलती को अपराध साबित करने की दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो गलती लोकतांत्रिक व्यवस्था की बन सकती है।

आज मोदी सरकार के सामने यही सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न है

वया वह असहमति को दुरमनी मानने की राजनीति से बाहर निकलकर संवाद की राजनीति को मजबूत करेगी? वया पुलिस और प्रशासन को यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार की आलोचना अपराध नहीं है? वया छात्रों को यह भरोसा दिया जाएगा कि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं? वया पत्रकारों को यह भरोसा मिलेगा कि सत्ता से कठिन सवाल पूछने के बावजूद उनका कैमरा सुरक्षित रहेगा? और वया सरकार यह स्वीकार करेगी कि सबसे बड़ी सरकार वह नहीं जो

विरोध को रोक दे बल्कि वह है जो विरोध के बीच भी अपना जनविश्वास बनाए रखे? आज सवाल मोदी के खिलाफ नहीं है सवाल मोदी सरकार से है। गलती किसकी है अगर पुलिस की है तो पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर तकनीक की है तो तकनीक की जांच क्यों नहीं? अगर प्रशासन की है तो प्रशासन जवाबदेह क्यों नहीं? अगर राजनीतिक प्रबंधन की है तो उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर इन सबमें कोई गलती नहीं है तो फिर देश में हर कुछ दिनों बाद यही सवाल क्यों खड़ा हो रहा है?

यहीं मोदी सरकार के सामने असली राजनीतिक चुनौती दिखाई देती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के सामने सवाल उठता है कि देश में संस्थाओं की जवाबदेही का राजनीतिक वातावरण कैसा बनाया जा रहा है? क्योंकि मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी राजनीतिक निर्णायकता रही है। लेकिन निर्णायकता और कठोरता में बहुत महीन फर्क होता है। निर्णायक सरकार वह है जो फैसला करती है। कठोर सरकार वह है जो दिखाई देने लगती है जो सवालियों को सहन नहीं करती। और लोकतंत्र में जनता को पहली वाली सरकार चाहिए दूसरी वाली

नहीं। मोदी सरकार को यह समझना होगा कि आज विपक्ष सिर्फ संसद में नहीं है। आज विपक्ष का एक हिस्सा सड़कों पर है एक हिस्सा विधेयविधालयों में है एक हिस्सा सोशल मीडिया पर है और एक हिस्सा पत्रकारों के कैमरों के पीछे खड़ा है। हर सवाल विपक्ष का सवाल नहीं होता हर प्रदर्शन राजनीतिक साजिश नहीं होता हर प्रदर्शनकारी अपराधी नहीं होता और हर पत्रकार सरकार विरोधी नहीं होता यही वह बिंदु है जहां सरकार की राजनीतिक समझ की असली परीक्षा होती है।

किस आधार कानूनी विमर्श का हिस्सा बनी 2,873 लोगों की सूची?

पुलिस ने यह जरूर कहा है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का परिणाम अंतिम प्रमाण नहीं है और हर नैप का फौलड वेरिफिकेशन किया जाना है। यही बात इस पूरे विवाद को और गंभीर बनाती है। अगर सिस्टम अंतिम प्रमाण नहीं है तो फिर 2,873 लोगों की सूची किस आधार पर राजनीतिक और कानूनी विमर्श का हिस्सा बनी? और अगर सिस्टम पर पूरा भरोसा किया जा सकता है तो जेल में बंद लोगों के चेहरे प्रदर्शन स्थल पर कैसे पहुंच गए? यह सवाल सिर्फ छात्रों का नहीं है। यह सवाल हर उस नागरिक का है जो कल किसी प्रदर्शन में खड़ा होगा और जिसके चेहरे को कोई मशीन किसी पुराने रिकॉर्ड से जोड़ सकती है।

उपफ... निशू आजाद

छात्र आंदोलन के दौरान निशू आजाद के पिता संजय कुमार पर हमला हुआ। इस मामले में स्वतंत्र भारद्वाज का नाम सामने आया। भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में हमले की बात स्वीकार करते हुए राक्षसी दम भरा और अपराध राजनीतिक संबंधों को कड़क अंदाज में गिनया और गिरफ्तारी से बचने का दावा भी किया। अब यहां भी सवाल वही है कि कानून सबके लिए एक है या कानून तक पहुंचने की रफ्तार राजनीतिक पहचान से बदलती है। क्योंकि सरकार की साख सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि उसने कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया। सरकार की साख इस बात से भी बनती है कि जनता का कानून पर कितना भरोसा बड़ा। गिरफ्तारी चेहरे विचार धर्म राजनीतिक पहचान या सत्ता से नजदीकी देखकर नहीं कानून के आधार पर होनी चाहिए।

बंद स्कूल खुलेगा तो पीडीए पढ़ेगा : अखिलेश यादव

शिक्षक दिवस पर सपा प्रमुख का योगी सरकार पर हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बंद किए गए प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही शोषित, वंचित, गरीब और पीड़ित समाज में सामाजिक-राजनीतिक चेतना और जागरूकता पैदा कर सकती है। इसी संदेश के साथ समाजवादी पार्टी शुक्रवार को प्रदेश के बंद प्राथमिक विद्यालयों में 'पाठशाला पुकारे' कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी का नारा है 'बंद स्कूल खुलेगा, तो पीडीए पढ़ेगा'।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्टर जारी कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि उग्र में जो 26 हजार प्राथमिक विद्यालय भाजपा सरकार ने बंद किए हैं, उन सभी स्कूलों में समाजवादी पार्टी आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन 'पाठशाला पुकारे' कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसका मूल उद्देश्य ये संदेश देना है कि 'बंद स्कूल खुलेगा, तो पीडीए पढ़ेगा'।

सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि इस कार्यक्रम के पीछे मूल भावना ये है कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि शिक्षा से ही शोषित-वंचित, गरीब-पीड़ित समाज में वो सामाजिक-राजनीतिक चेतना और जागरूकता आएगी जो प्रभुत्ववादियों के वर्चस्व को चुनौती देकर भेदभाव को खत्म करेगी, बराबरी लाएगी और समता-समानता पर आधारित 'सामाजिक न्याय का राज' लाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएगी, हमारे 'बंधु राष्ट्र' के संकल्प को साकार कर दिखाएगी।



सरकार बनी तो फिर खुलेंगे बंद स्कूल

इसके पहले अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर बंद किए गए 26 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने के बजाय सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, जिसका सबसे अधिक असर पीडीए वर्ग के विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा से ही वंचित और पिछड़े समाज में जागरूकता और सामाजिक चेतना पैदा होगी तथा बराबरी और सामाजिक न्याय की दिशा मजबूत होगी।

अखिलेश यादव से पीएचडी उपाधिप्राप्त मेधावी छात्रों ने मिलकर आशीर्वाद लिया

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पीएचडी उपाधिप्राप्त दो मेधावी छात्रों ने मिलकर आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव ने उनको बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश महासचिव जयवीर सिंह पासी ने बाबा साहब भीमराव

अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से शिक्षा शास्त्र विभाग से शोध कार्य किया है। काशी विद्यापीठ, वाराणसी से नेताजी श्री मुलायम सिंह पर अपना शोध प्रबंध श्री आलोक सौरभ पाण्डेय ने श्री अखिलेश यादव को समर्पित किया। आलोक सौरभ पाण्डेय को अपने शोधकार्य पर पीएचडी उपाधि मिली है।

बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला नकारात्मक राजनीति का हिस्सा : त्यागी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने उत्तर प्रदेश में मायावती की आगामी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति, सपा के पीडीए को लेकर ओपी राजभर के बयान, आरक्षण पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी और राम मंदिर ट्रस्ट में पहली महिला सदस्य के शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तेलंगाना कैबिनेट से कोंडा सुरेखा को हटाए जाने और अभिनेत्री स्वरा भास्कर के एक बयान पर भी अपनी बात रखी।

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर केसी त्यागी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी परिस्थितियों और रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने मायावती के इस फैसले को नकारात्मक राजनीति का हिस्सा बताया। त्यागी ने कहा कि चुनावी रणनीति तय करना हर पार्टी का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दलों को व्यापक राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर द्वारा समाजवादी पार्टी के पीडीए में पी का अर्थ पहली हार बताए जाने पर भी केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी समय-समय पर पीडीए की अलग-अलग व्याख्या करते रहे हैं और इसके शब्दों के अर्थ बदलते रहे हैं।

तेलंगाना कैबिनेट से कोंडा सुरेखा को हटाए जाने के फैसले पर केसी त्यागी ने कहा कि उनकी बेटी को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए थे। कोंडा सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाया जाना उन्हीं विवादों के परिणामस्वरूप हुआ है।



स्वरा भास्कर कर चुकी हैं अपने बयान का खंडन

श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में पहली महिला सदस्य को शामिल किए जाने के फैसले का आरएलडी नेता ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को ओर बल मिलेगा। धार्मिक और सार्वजनिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सकारात्मक कदम है। उन्होंने ट्रस्ट में महिला प्रतिनिधित्व को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा हिंदू महिलाओं और जौहर को लेकर दिए गए बयान पर केसी त्यागी ने कहा कि स्वरा भास्कर ने बाद में अपने बयान का खंडन किया है। उनके खंडन पर विश्वास किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह सती प्रथा के खिलाफ है।

परिणामस्वरूप हुआ है। आरक्षण को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी पर केसी त्यागी ने स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि वे अनिरुद्धाचार्य के विचारों से सहमत नहीं हैं। त्यागी ने संविधान में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण व्यवस्था संवैधानिक आधार पर मौजूद है। इसलिए इस मुद्दे पर संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखना जरूरी है।

बुलंदशहर से पकड़ा गया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज

सीजेपी प्रोटेस्ट में निशु आजाद के पिता का सिर फोड़ने का आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर हुए भारी हंगामे और विरोध-प्रदर्शन के बाद बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमले के आरोपी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में ले लिया है।

यह पूरा मामला एक वायरल वीडियो के बाद सुर्खियों में आया था, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज खुद दावा कर रहा था कि उसने



सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान निशु के पिता का सिर फोड़ दिया था। वीडियो में उसने डींग मारते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने उसके राजनीतिक संबंधों की वजह से उसे छोड़ दिया। वायरल क्लिप में भारद्वाज कह रहा है कि संजय कुमार के सिर पर गंभीर चोट आई और उन्हें 60 टांके लगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सीजेपी

पुलिस के सामने रखी गयी कई मांगें

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि संगठन ने पुलिस के सामने कई मांगें रखीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संजय कुमार के सिर में इतनी गंभीर चोट लगी है तो एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद एक पॉइकास्ट इंटरव्यू में हत्या के प्रयास का दावा किया है, इसलिए मामले में संबंधित धारा जोड़नी चाहिए। संगठन ने दलित परिवार से जुड़ा मामला होने के कारण एससी-एसटी एक्ट की धाराओं को सख्ती से लागू करने और घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेता अमिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी कानूनी टीम मेजी, जबकि सीजेपी के वकील प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल डीसीपी से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की।

और कई विपक्षी दलों ने दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। संगठन का कहना था कि राजधानी के बीचों-बीच एक दलित परिवार पर हमला हुआ और आरोपी खुलेआम घूम रहा है।

इसी को लेकर शुक्रवार को सीजेपी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन

में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 72 घंटे के अंदर आरोपी को पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं में गिरफ्तार करने का भरोसा दिया था।

शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर : तनुज पुनिया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। चौथे दिन धरने का नेतृत्व कर रहे अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन एवं सांसद श्री तनुज पुनिया ने कहा कि भाजपा, आरएसएस की शुरु से ही मानसिकता दलित विरोधी रही है। उसी दलित विरोधी मानसिकता के चलते केन्द्र की मोदी सरकार दलितों के प्रति अपमानजनक और उन्नीतनात्मक रवैया अपनाने लगी है।

भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ाकर बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं एवं दलित वर्ग से आते हैं इसलिए उनकी हल्द्वानी में जनसभा के बाद भाजपा के लोगों द्वारा मंच का शुद्धिकरण किया जाना पूरी तरह संविधान विरोधी कृत्य है। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार इस संविधान विरोधी कृत्य के दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही नहीं करती तथा इस दलित विरोधी कृत्य के खिलाफ आवाज उठाने पर हमारे नेता राहुल गांधी के विरुद्ध फर्जी दर्ज किए गए एफआईआर को निरस्त नहीं करती।



यूपी से भाजपा की विदाई, झूठ की एक्सपायरी डेट आ गई : राजीव शुद्धिकरण विवाद दलित समाज के आत्मसम्मान का मामला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद राजीव राय ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की झूठ की एक्सपायरी डेट आ गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। सपा सांसद का यह बयान उस वक्त आया है जब सीएम योगी ने पूर्व की अखिलेश यादव की सरकार पर हमला बोला।

मथुरा में सीएम योगी ने कहा कि सनातन को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट्टी में मिल गए। उन्होंने अयोध्या और काशी की तर्ज पर मथुरा



में भी भव्य धाम विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट की जा चुकी हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया

कि पहले की सरकारों को अपने वोट बैंक की चिंता रहती थी और इसी वजह से ब्रज क्षेत्र में आने से डरते थे। पिछली सरकारों के कार्यकाल में जवाहरबाग जैसी घटनाएं हुईं, जबकि अब ब्रज में ऐसे विवादों के बजाय रंगोत्सव और ब्रजराज उत्सव जैसे आयोजन हो रहे

हैं। सीएम योगी के बयान पर सपा सांसद ने कहा कि भाजपा दहशत में है। उसे सपने में भी अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है और भाजपा की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है।

यूपी विस-27 चुनाव पर बिछने लगी बिसात

सभी सियासी दलों ने शुरू की जोर आजमाइश

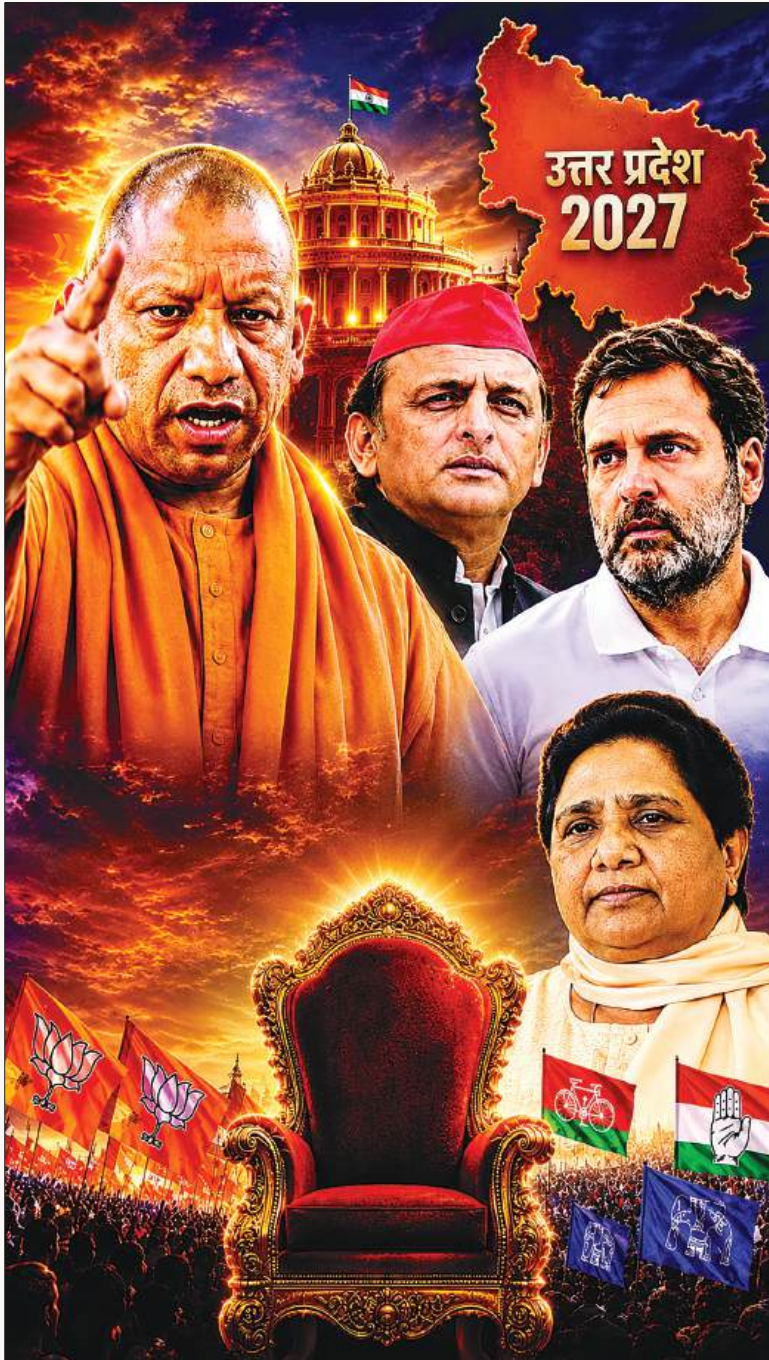
- » कांग्रेस-सपा के निशाने पर योगी सरकार
- » नेता प्रतिपक्ष ने यूपी सरकार पर साधा निशाना छोटे दलों ने भी शुरू की तैयारी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। जैसे-जैसे यूपी में विस-27 चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे यहां के सियासी दलों में सक्रियता बढ़ गई है। जहां बसपा ने अपने बूथों की तैयारी सैक्टरों के उपर ला दिया है। वहीं कांग्रेस व सपा भाजपा सरकार को घेरने में लगी हैं। सपा ने तो पोस्टरों जरिये हमला शुरू कर दिया है। इस बीच छोटे दल भी तैयारी होने लगे हैं। वहीं कांग्रेस व सपा सबसे ज्यादा भाजपा हमला वर है। हालांकि भाजपा भी इन दोनों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उधर नेता प्रतिपक्ष लोस राहुल गांधी ने दिल्ली-एनसीआर में स्लीपर बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप की घटना पर केंद्र, दिल्ली और यूपी सरकारों

पर करारा वार किया। उन्होंने इसे निर्भया कांड के बाद भी महिला सुरक्षा में सरकार की अक्षमता और पुलिस की घोर लापरवाही का परिणाम बताया, जो 47 किलोमीटर तक बस के बेरोकटोक चलने से उजागर हुई। यह घटना प्रशासन की नाकामियों पर पर्दा डालने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में महिला सुरक्षा एक गंभीर चिंता बन गई है।

उधर बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने इस बयान को लेकर एसपी एमएलसी पर तीखा हमला बोला। अवस्थी ने कहा जल्द ही, सभी कुत्ते पट्टे बंधे हुए एसपी दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। इससे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान कोई नहीं कर सकता। जनता हमें चुनावों में जवाब देगी।



उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नाकाम : राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस में 17 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना को लेकर केंद्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों की आलोचना की। गांधी ने इस बात पर पुलिस की नाकामी की आलोचना की कि स्लीपर बर्थ पर पर्दे लगे होने के बावजूद बस

को किसी भी चेकपॉइंट पर नहीं रोका गया। उन्होंने इसे दिल्ली में 12 के निर्भया मामले के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा करने में सरकार की अक्षमता का सबूत बताया। एक पोस्टर में गांधी ने लिखा कि दिल्ली- एनसीआर महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो गया है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही एक स्लीपर बस में

एक नाबालिग लड़की के साथ 47 किलोमीटर तक गैंगरेप हुआ। हैरानी की बात है कि न तो दिल्ली पुलिस और न ही नोएडा पुलिस को इसकी ज़र्रा भी भनक लगी। यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली की रिंग रोड और बॉर्डर से गुजरी, लेकिन किसी भी चेकपॉइंट पर इसे एक बार भी नहीं रोका गया।

अपराधियों को प्रशासन का जरा भी डर नहीं रहा

उन्होंने बताया कि बस की सीटों पर पर्दे लगे हुए थे ताकि अंदर क्या हो रहा है, यह कोई देख न सके। उन्होंने आगे कहा कि और अपराधियों को प्रशासन का जरा भी डर नहीं था। निर्भया कांड के इतने सालों बाद और ऐसी कई घटनाओं के बावजूद, ऐसी बसों की चेकिंग और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? वे पर्दे सिर्फ उस एक बस में नहीं लगे थे - वे सरकार द्वारा प्रशासन की नाकामियों पर साल-दर-साल डाले गए पर्दों का नतीजा हैं, जिसकी वजह से महिलाएं देश की राजधानी में सुरक्षित सफ़र भी नहीं कर पा रही हैं।

अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं

अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि केंद्र और राज्य सरकारों के इस सिस्टम को ठीक करने से पहले और कितनी महिलाओं और लड़कियों को यह सब सहना पड़ेगा? क्या अमित

शाह के अंडर दिल्ली पुलिस या आदित्यनाथ के अंडर यूपी पुलिस की कोई जवाबदेही तय होगी? बिल्कुल नहीं - इस अपराध पर भी बस पर्दा डाल दिया जाएगा। 17 साल की लड़की ने आरोप

लगाया कि 4 अगस्त की रात उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से नोएडा जाते समय बस के अंदर उसके साथ गैंगरेप किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

बसपा का जल्द टिकट तय करने पर जोर

बहुजन समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर माह में अपने अधिकांश टिकट फाइनल करने की तैयारी में है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को यूपी के सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने अन्य दलों की चुनावी रेवड़ियों से सावधान रहने को कहा। खासकर महिलाओं को भाजपा और सपा द्वारा हर साल हजारों रुपये देने के प्रलोभन से आगाह किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जेन जी की समस्याओं का समर्थन करते हुए सरकारों से उनका निस्तारण करने को कहा। बसपा सुप्रीमो ने बैठक में कहा कि यूपी की जनता विरोधी पार्टियों के ऐसे खुल्लमखुल्ला छलावों व विश्वासघात आदि से बचें और चुनाव में अपनी मर्जी के हिसाब से निष्पक्ष होकर वोट करें। देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव के बाद सरकार बन जाने पर ऐसी ही लगातार वादाखिलाफी और विश्वासघात जारी है।

बसपा के संघर्ष के साथ जेन-जी और जेन-अल्फा तक को ऐसे जनविरोधी रवैयों के कारण संघर्ष करना पड़ा जिसके बाद उन्हें पुलिस के मुकदमे आदि जैसे सरकारी दमन का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में प्रदेश के लोगों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन की वजह से मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। सरकार जो भी घोषणाएं कर रही है वह ऊट के मुंह में जीरा के समान हैं।

कुत्ते वाले बयान पर बवाल

समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव की पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में की गई एक विवादित टिप्पणी से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि हालात चाहे जैसे भी हों, वोटर को अखिलेश यादव का समर्थन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह किसी कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें, तब भी आपको उन्हें ही वोट देना होगा, क्योंकि वही आपकी



समस्याओं का समाधान करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में भूल जाइए, वह व्यक्ति बहुत महान है। इन बयानों पर राजनीतिक पार्टियों की तीखी प्रतिक्रिया आई है; बीजेपी ने एसपी नेता पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस विवाद से खुद को अलग करने की कोशिश की है।

लोकतंत्र का अपमान कर रही सपा : आलोक अवस्थी

बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने इस बयान को लेकर एसपी एमएलसी पर तीखा हमला बोला। अवस्थी ने कहा जल्द ही, सभी कुत्ते पट्टे बंधे हुए एसपी दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। इससे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान कोई नहीं कर सकता। जनता हमें चुनावों में जवाब देगी। वहीं, एसपी नेता दीपक रंजन ने इस विवाद को ज्यादा तूल नहीं दिया और कहा कि इस बयान को जरूरी नहीं कि पार्टी



से ही जोड़ा जाए। रंजन ने कहा लोकतंत्र में जनता के पास रिकॉर्ड होता है कि कौन जीतता है, और हमें इस बात पर नहीं पड़ना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं। ये उनके निजी बयान हो सकते हैं।

बीजेपी को इस बयान से क्यों दिक्कत : सुरेंद्र राजपूत

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इस बयान पर बीजेपी की आपत्ति पर सवाल उठाए। राजपूत ने कहा, बीजेपी को इस बयान से क्या दिक्कत है? वे आपस में बात कर रहे हैं। आपके नेताओं को ठाकुरों और पंडितों के दलित बनने से कोई

दिक्कत नहीं है। बीजेपी को दूसरे नेताओं से दिक्कत है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब



अखिलेश यादव ने 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बूथ-स्तर पर अभियान शुरू किया है। वे बीजेपी सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं और इसे राज्य के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी (सपा), जिसने 22 के

विधानसभा चुनावों में 111 सीटें जीती थीं, 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली सफलता को आगे बढ़ाना चाहती है। लोकसभा चुनावों में पार्टी 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

घोषणाओं से कब श्रमेव जयते सत्य होता रहेगा

यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए निगम बनाया गया है। इसके तहत श्रमिकों को बहुत सी योजनाएं देन की बात कही गई है। सवाल उठता है कि यह सब सुचारू रूप से चलता रहेगा या प्रशासनिक अनदेखी का शिकार हो जायेगा। भारत के श्रमिकों की वर्तमान में क्या स्थिति है इसके लिए नोएडा की हाल की घटना बहुत कुछ कह देती है। अपने देश में आज न्यूनतम वेतन के नाम पर मजदूर बस ठगे जाते हैं। सरकारें बड़े-बड़े दावे करते हैं पर उन दावों की सच्चाई मजदूरों के की मांगे व धरना प्रदर्शन बता देते हैं। सरकारों से एक ही मांग है जो मजदूर देश का निर्माण कर रहे हैं उनको हर प्रकार से सुविधा मिलनी चाहिए ताकि चह और मेहनत से देश सेवा में लग सकें। आखिर कब श्रमेव जयते सत्य होगा। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के द्वारा किया गया उद्धोष मजदूरों, दुनिया को एक करो, महज एक नारा नहीं था बल्कि विश्व निर्माण की आयोजना में श्रम और श्रमिकों के ऐतिहासिक अवदान को एक नए आर्थिक-राजनीतिक अर्थ-संदर्भ में देखने का एक भारतीय नजरिया था।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहाँ मार्क्सवाद के प्रभाव से दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ के नारे के माध्यम से श्रमिकों को वर्ग-संघर्ष के लिए लामबंद किया जा रहा था, वहीं भारतीय मजदूर संघ ने श्रम की अस्मिता को केंद्र में रखकर दुनिया को सँवारने का एक मानवीय, रचनात्मक और समरसता-पूर्ण विकल्प प्रस्तुत किया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के कम्युनिस्ट घोषणापत्र (1848) में उद्धृत दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं, और जीतने के लिए पूरा संसार है। निःसंदेह, श्रम और श्रमिकों के ऐतिहासिक शोषण और वंचना से उपजे आक्रोश को समेटे यह नारा, कामगारों के विभाजन और विभाजन के कारणों से हुई उनके श्रम की लूट और अस्मिता-हनन का ऐतिहासिक दस्तावेज है। जिसकी मूल प्रेरणा वर्ग-संघर्ष पर आधारित है, जो मजदूर वर्ग को पूंजीवाद एवं सामन्तवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील करता है। किन्तु ऐसा मान लेना एक ज्ञानमीमांसीय भूल ही होगी कि केवल श्रमिक स्वयं संगठित होकर ही आधुनिक अर्थ-तंत्र में पूंजीवाद के वर्चस्व से मुकाबला कर सकता है? इसके विपरीत, भारतीय सांस्कृतिक चेतना श्रम और श्रमिकों को आधुनिक पूंजीवाद की संकीर्ण दृष्टि से परे देखती है। मजदूरों, दुनिया को एक करो, यह वैचारिक परिवर्तन की एक कार्यात्मक परियोजना है, जो दुनिया को श्रमिक-केन्द्रित बनाती है।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

सिंधु जल विवाद केस जीतकर भी दुखी पाक

पुष्परंजन

नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) द्वारा सिंधु जल विवाद के एकतरफा फैसले पर पाकिस्तान बल्ले-बल्ले, शाबाश-शाबाश करने लगा है। हेग स्थित 'पीसीए' ने सोमवार को फैसला सुनाया है कि भारत एकतरफा तरीके से सिंधु जल संधि को सस्पेंड नहीं कर सकता। कोर्ट ने नई दिल्ली की उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया है, जिनका इस्तेमाल उसने छह दशक पुराने जल-बंटवारे के समझौते को अप्रैल, 2025 से 'स्थगित' रखने को सही ठहराने के लिए किया था। सोमवार को सुनाए गए सर्वसम्मत फैसले में पांच सदस्यीय कोर्ट ने पाया कि संधि 'पूरी तरह से लागू है' और भारत को इसके तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। इसमें पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी शामिल हैं।

पहलगाम हमला 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के बैसारन घास के मैदानों में हुआ था, जिसमें पाक-पोषित बंदूकधारियों ने बर्बरता से 26 लोगों की जान ले ली थी। बंदूकधारियों ने गोली दागने से पहले उनसे उनका धर्म पूछा था। इस नरसंहार के बाद, भारत ने कहा था कि वह संधि को तब तक सस्पेंड रखेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को 'विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय' रूप से खत्म नहीं कर देता। इस्लामाबाद इन आरोपों से इनकार करता है कि वह हमले के पीछे था। लेकिन माजी में दी उसकी धमकियों से कोई मानने को तैयार नहीं कि पहलगाम कांड में उसका हाथ नहीं रहा है। बहरहाल, पाकिस्तान द्वारा हेग में लाए गए सिंधु जल संधि मामले में भारत ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में जलविद्युत परियोजनाएं बनवाने वाला चीन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। माजी में चीन ने भी परमानेंट

कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के एक ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया था, जो दक्षिण चीन सागर के विवाद पर फिलीपींस के पक्ष में आया था। ऐसा नहीं कि नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भारत ने कोई केस लड़ा ही नहीं।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत अब तक 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का हिस्सा रहा है। मगर सवाल है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यदि पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुना भी दिया, तो उसे लागू कैसे करवाएगा? भारत ने कुछ ही घंटों में इस फैसले को खारिज कर दिया था। यह दिलचस्प है कि 1 सितंबर, 2026 को किर्गिस्तान के

जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है। उन्होंने कहा, 'अगर वे कहते हैं कि वे पानी नहीं बहने देंगे, तो वे खुद ही बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि भारत के बांध रन-ऑफ-रिवर हाइड्रोपावर प्लांट हैं, जिनमें पानी जमा करने की जगह बहुत कम होती है।' अब्बास ने कहा, 'एक बार जब उनके बांध भर जाते हैं, तो उनके पास पानी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।' लेकिन हाइड्रोलॉजी और जल संसाधन विशेषज्ञ हसन अब्बास ने पाकिस्तान के अपने जल प्रबंधन की भी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लामाबाद का नए बड़े बांधों पर जोर देना सस्ते समाधानों को नजरअंदाज करता है। जल विशेषज्ञ अब्बास ने कहा



बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक ही मंच पर मौजूद रहे, लेकिन दोनों में न बात हुई, न इस विषय पर कोई चर्चा। हालांकि, इस्लामाबाद में रहने वाले हाइड्रोलॉजी और जल संसाधन विशेषज्ञ हसन अब्बास इस बात से सहमत नहीं थे कि समझौते के टूटने से फिलहाल पाकिस्तान के लिए कोई तत्काल खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा खतरा है। पश्चिमी नदियां भौगोलिक स्थिति की वजह से सुरक्षित हैं, न कि मुख्य रूप से संधि की वजह से।' हसन अब्बास ने बताया कि चिनाब नदी पर भारत की स्टोरेज क्षमता लगभग 1 मिलियन एकड़-फीट (405,000 हेक्टेयर-फीट) है, जो पाकिस्तान की मौसमी सिंचाई की

कि सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर नए जलाशयों की तुलना में कहीं ज्यादा पानी बचाया जा सकता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी की मुख्य धारा पर वर्तमान में कई प्रमुख मेगा जलविद्युत और बांध परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें दासू और दियामेर-भाशा जैसी बड़ी परियोजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं।

दासू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिंधु नदी पर बन रहा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। उसी तरह दियामेर-भाशा बांध गिलगित-बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर सिंधु नदी पर रोलर-कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से बन रहा 272 मीटर ऊंचा विशाल बांध है। इसके अलावा सिंधु नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों पर अन्य छोटी-बड़ी जलविद्युत एवं सिंचाई परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं।

डॉ. शशांक द्विवेदी

एआई को लेकर मैं सबसे बड़ा डर यही रहा है कि मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी। चैटबॉट से लेकर जनरेटिव एआई तक, तकनीक जिस तेजी से विकसित हुई है, उसने इस आशंका को और गहरा किया है। वैश्विक वित्तीय संस्था नोमुरा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से अगस्त, 2026 के बीच भारत में एआई से संबंधित करीब 83,100 नौकरियां पैदा हुईं, जबकि एआई से जुड़ी 31,921 नौकरियां छंटनी या कर्मचारियों की कमी के रूप में प्रभावित हुईं। अर्थात, हर एक प्रभावित नौकरी के मुकाबले लगभग 2.6 नई एआई-संबंधित नौकरियां बनीं। मगर यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि एआई रोजगार की समस्या समाप्त कर रहा है। एआई नई नौकरियां जरूर बना रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिन लोगों की पुरानी नौकरियां जा रही हैं, वही लोग नई नौकरियों में प्रवेश कर पा रहे हों। यही भारत के सामने उभरती सबसे बड़ी रोजगार चुनौती है। ?

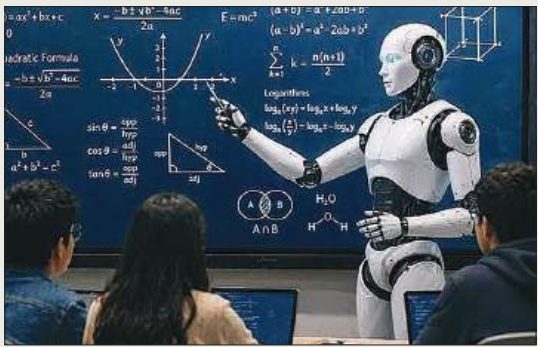
नोमुरा के अनुसार, भारत में एआई अपनाने से एक 'दो-स्तरीय रोजगार बाजार' उभर रहा है। एक तरफ अनुभवी कर्मचारियों की मांग बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ फ्रेजरर्स के लिए अवसर अपेक्षाकृत कम हो रहे हैं। भारतीय आईटी क्षेत्र की 651 कंपनियों पर किए गए आईसीआरआईआईआर के सर्वेक्षण में 55 प्रतिशत कंपनियों ने बताया कि उनकी एंटी-लेवल भर्ती में कमी आई है। इसके मुकाबले मिड-लेवल भर्ती में कमी बताने वाली कंपनियों का अनुपात 25 प्रतिशत और वरिष्ठ स्तर पर केवल 14 प्रतिशत था। भारत की आर्थिक ताकत का एक बड़ा आधार हर वर्ष कॉलेजों और

एआई युग में नौकरी मिलने-खोने के यक्ष प्रश्न

वैश्विक वित्तीय संस्था नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से अगस्त, 2026 के बीच भारत में एआई से संबंधित करीब 83,100 नौकरियां पैदा हुईं, जबकि एआई से जुड़ी 31,921 नौकरियां प्रभावित हुईं। मगर यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि एआई सिर्फ रोजगार बढ़ा रहा है।

विश्वविद्यालयों से निकलने वाली विशाल युवा आबादी है। यदि कंपनियां पहले की तरह बड़ी संख्या में फ्रेजरर्स को नियुक्त नहीं करती तो समस्या केवल बेरोजगारी की नहीं होगी, बल्कि 'करिअर की पहली सीढ़ी' के कमजोर पड़ने की होगी।

दरअसल, पारंपरिक कॉर्पोरेट व्यवस्था में एक युवा कर्मचारी सामान्य काम से शुरुआत करता था। वह डेटा तैयार करता था, रिपोर्ट बनाता था, बेसिक कोड लिखता था, गुणवत्ता जांच करता था, ग्राहक सेवा संभालता था और धीरे-धीरे अनुभव हासिल करके जिम्मेदार पदों तक पहुंचता था। एआई इन शुरुआती कार्यों का एक बड़ा हिस्सा तेजी से करने लगा है। नोमुरा ने स्टाफिंग फर्म स्कैनो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय आईटी कंपनियों की नेट हार्यरिंग वित्त वर्ष



2021-22 में लगभग छह लाख थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर करीब 1.40 लाख रह गई। कंपनियां बड़े पैमाने पर कैंपस भर्ती करने के बजाय कम, लेकिन कुशल कर्मियों को प्राथमिकता दे रही हैं। यहां एआई को अकेला दोषी मानना भी उचित नहीं होगा। वैश्विक मांग, आईटी उद्योग का पुनर्गठन, लागत नियंत्रण और ऑटोमेशन जैसे कई कारक इस बदलाव के पीछे हैं। लेकिन एआई ने इस परिवर्तन की गति निश्चित रूप से बढ़ा दी है।

लेकिन अगर एआई नई नौकरियां बना रहा है तो वे नौकरियां किसके लिए हैं? एआई मॉडल विकसित करने वाले इंजीनियर, डेटा विशेषज्ञ, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, एआई ट्रेनर, डेटा एनोटेटर, भाषा विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एआई सिस्टम को व्यवसाय

से जोड़ने वाले पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। नोमुरा के एशियाई अध्ययन में एआई से संबंधित नई नौकरियों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में केंद्रित था। इसका अर्थ यह है कि भारत के सामने अब केवल 'कितनी नौकरियां?' का सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है—'किस कौशल वाली कितनी नौकरियां?' आने वाले वर्षों में एआई का असली मुकाबला उन कर्मचारियों के बीच होगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं और उन कर्मचारियों के बीच जो इसे केवल अपने रोजगार के लिए खतरा मानते हैं। एक अकाउंटेंट जो एआई आधारित विश्लेषण, ऑटोमेशन और डेटा टूल का उपयोग कर सकता है, उसकी उपयोगिता उस अकाउंटेंट से अधिक हो सकती है जो केवल पारंपरिक तरीके से काम करता है।

इसी तरह एक पत्रकार जो शोध, डेटा विश्लेषण और प्रारंभिक ड्राफ्टिंग के लिए एआई का प्रभावी इस्तेमाल कर सकता है, वह तकनीक से प्रतिस्थापित होने के बजाय तकनीक की उत्पादकता बढ़ाने वाला पेशेवर बन सकता है। इसलिए भारत को 'एआई के साथ रोजगार' की रणनीति बनानी होगी। निस्संदेह, एआई युग में रोजगार का स्वरूप बदलने जा रहा है। संभव है कि भविष्य में एक कर्मचारी वही काम करे जो आज तीन लोग करते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे नए काम भी पैदा हों जिनकी आज कल्पना तक नहीं की गई है। आज देश के पास विशाल युवा आबादी, मजबूत आईटी उद्योग, अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं की क्षमता और दुनिया के लिए डिजिटल सेवाएं देने का अनुभव है। यदि इन ताकतों को एआई कौशल के साथ जोड़ा जाए तो भारत एआई-आधारित रोजगार का वैश्विक केंद्र बन सकता है।

आजकल मोबाइल के बिना छोटे बच्चे भी रहते नहीं है और फोन में कार्टून देखकर ही खाना खाते हैं। मोबाइल फोन के बिना जैसे उनकी लाइफ ही नहीं है, फोन उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। बच्चों के घरों में फोन, टैबलेट या टीवी के ज्यादा देखने की वजह से घरों में काफी बहस भी होती है और जैसे ही आप स्क्रीन बंद करते हैं या बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनते हैं, उनका रोना-धोना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं कि उम्र में ही बच्चों लड़ने-झड़ने लगते हैं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरा ही बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप गलत है। क्योंकि आजकल हर दूसरे बच्चे की समस्या है। आज कई माता-पिता बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, लेकिन सख्ती या अचानक फोन छीनने से स्थिति और बिगड़ जाती है। अगर आप भी अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि उन पर सीधे रोक लगाने की बजाय आप उनको प्यार और मजेदार एक्टिविटी के साथ उनका रूटीन बदल सकते हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे आसान तरीके, जिनसे बिना लड़ाई-झगड़े के बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया जा सकता है।



स्क्रीन टाइम का टाइम डिसाइड करें

बच्चे जब मन करे तब फोन या टीवी देखने लगें, तो स्क्रीन टाइम कम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिन में स्क्रीन देखने के लिए दो से तीन निश्चित समय तय करें। जैसे- लंच के बाद 30 मिनट या होमवर्क पूरा करने के बाद 45 मिनट। बच्चे को पहले से बता दें कि उसे कब स्क्रीन मिलेगी। आप इसके लिए एक छोटा सा टाइम-टेबल भी बना सकते हैं, जिसमें खाने, खेलने, पढ़ने और स्क्रीन टाइम का समय लिखा हो। इससे बच्चे को यह फील नहीं होगा कि उससे फोन छीना जा रहा है, बल्कि उसे पता रहेगा कि स्क्रीन देखने का उसका समय कब आएगा।

इस तरह कम करें

बच्चों का स्क्रीन टाइम

अचानक फोन न छीनें, पहले दें चेतावनी

बच्चा किसी वीडियो या गेम में बिजी हो और अचानक फोन बंद कर दिया जाए, तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। इसलिए स्क्रीन टाइम खत्म होने से पहले उसे धीरे-धीरे तैयार करें। पहले 10 मिनट बाकी होने की जानकारी दें। फिर 5 मिनट और आखिर में 2 मिनट की चेतावनी दें। आप बच्चे के साथ मिलकर टाइमर भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बताएं कि फोन बंद करने के बाद क्या करना है, जैसे- टाइमर बजने के बाद हम बाहर गेंद खेलेंगे या इसके बाद तुम अपनी ड्राइंग पूरी कर सकते हो। इस तरह स्क्रीन हटाने के बजाय बच्चे का ध्यान किसी दूसरी एक्टिविटी की ओर आसानी से मोड़ा जा सकता है।

घर में कुछ जगहों और समय को स्क्रीन-फ्री रखें

स्क्रीन टाइम कम करने के लिए पूरे घर में नियम बनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कुछ खास जगहों और समय से करें। जैसे डाइनिंग टेबल पर फोन नहीं चलेगा, बेडरूम में स्क्रीन नहीं होगी और सुबह उठने के बाद या सोने से पहले कुछ समय फोन से दूरी रहेगी। इन नियमों को बच्चे के लिए सजा की तरह न बनाएं। इसे पूरे परिवार का नियम बनाएं। अगर माता-पिता भी खाने के समय फोन दूर रखेंगे, तो बच्चे के लिए रूल फॉलो करना आसान होगा।

स्क्रीन के बदले मजेदार चीजें पहले से तैयार रखें

अगर आप बच्चे से सिर्फ यह कहेंगे कि अब टैबलेट बंद करो, लेकिन उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं देंगे, तो वह दोबारा स्क्रीन देखने की मांग करेगा। इसलिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्क्रीन के बदले उनको दूसरी एक्टिविटी में बिजी करें। बच्चों को पजल, ड्राइंग, कलरिंग, ब्लॉक्स, बोर्ड गेम, गेंद खेलने या छोटी-सी क्राफ्ट एक्टिविटी में लगाया जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए शेप मैचिंग, बीड्स को अलग-अलग करना, ड्राइंग या खिलौनों को ठीक से रखने जैसी एक्टिविटी भी अच्छी हो सकती हैं। कोशिश करें कि अगली एक्टिविटी बच्चे को मजेदार लगे, ताकि उसे स्क्रीन से दूर जाना सजा जैसा महसूस न हो।

प्यार से बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें

स्क्रीन टाइम कम करते समय बच्चे का नाराज होना, रोना या जिद करना नॉर्मल हो सकता है। ऐसे समय पर उसके गुस्से को समझें, लेकिन तय नियम को बार-बार न बदलें। अगर बच्चा रोता है और आप उसके स्क्रीन टाइम को बढ़ा देते हैं तो इससे उसको लगने लगता है कि रोने से प्रेशर बनता है।

सबसे जरूरी है माता-पिता की कॉमिटेमेंट

बच्चों की स्क्रीन की आदत एक दिन में नहीं बदलेगी। शुरुआत में वे विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन टाइम का समय तय हो, स्क्रीन बंद करने से पहले चेतावनी मिले और उसके बाद मजेदार ऑप्शन मौजूद हों, तो धीरे-धीरे यह नई लाइफस्टाइल काका हिस्सा बन सकता है।



हंसना मना है

मास्टर जी : बताओ, टाइगर ब्रिस्कट पर जो ग्रीन डॉट होता है, उसका क्या मतलब होता है? स्टूडेंट : सर, इसका मतलब है कि टाइगर ऑनलाइन है....!!!

साली ने जीजा से पूछा : क्या आप जर्मन भाषा पढ़ सकते हो? जीजा ने कहा : क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ साली- वो कैसे जीजा जी? जीजा : बस जर्मन भाषा हिंदी या अंग्रेजी में लिखी हो तब पढ़ सकता हूँ।

पापा : बेटा तुम चाहे पास हो या फेल मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा, बेटा : थैंक्स पापा, आप बहुत अच्छे हैं। पापा : पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए....

लड़की : स्टेशन तक के कितने पैसे लगे? रिक्शावाला : मैडम बीस रुपये। लड़की (हैरान) : स्टेशन के बीस रुपये? रिक्शावाला : हां मैडम। लड़की : अरे.... ये तो रहा स्टेशन रिक्शावाला- मैडम हाथ पीछे कर लो, कहीं रेल के नीचे ना आ जाएं।

कहानी

राजा का आदेश

बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर में राजा तेज प्रताप सिंह का राज्य था। वे बहुत दयालु एवं परोपकारी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। सभी लोग धनवान थे। किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं थी। सभी मिलजुलकर रहते थे। एक बार राजा तेज प्रताप सिंह जंगल में घूमने गये। वहां उन्होंने तरह तरह के जानवर देखे। शेर, चीते, भालू, हिरन और खरगोश देखने में बहुत सुन्दर लग रहे थे। राजा ने सोचा, इतने सुन्दर जानवरों को चंदनपुर के लोग देखेंगे, तो बहुत खुश होंगे। इसलिए राजा ने जानवरों से कहा कि वे चंदनपुर चलें। चंदनपुर में उनका विशेष ध्यान रखा जायेगा। हिरन और खरगोश डर के कारण चंदनपुर नहीं आये। शेर, चीते और भालू चंदनपुर आ गये। लोगों ने उन्हें देखा तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे उन्हें देखकर खुश भी हुए किन्तु उनको थोड़ा थोड़ा डर भी लगा। रात को जब सभी लोग सो जाते, तब शेर, चीते और भालू किसी की गाय, किसी की भैंस और किसी की बकरी को खा जाते। जब लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने राजा से शेर, चीते और भालू की शिकायत की। राजा ने कहा जो मिलजुलकर नहीं रहे और दूसरों का नुकसान करे उसको दूर भगा देना ही ठीक रहता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शेर, चीते और भालू को जंगल की ओर भगा दें। सैनिकों ने तीर मारकर शेर, चीते और भालू को जंगल की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया। जो दूसरों का नुकसान करे, उसको अपने साथ कोई भी नहीं रखना चाहेगा। शेर, चीते और भालू अब जंगल में ही रहते हैं। उनके जाने के बाद चंदनपुर के लोग फिर से सुख से रहने लगे।

5 अंतर खोजें



पंडित संदीप आनंद शर्मा

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



मेघ

आपको संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा? आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे, आपको उनमें खींचा जाएगा? कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे ?



तुला

नौकरी में आत्मबल मजबूत रहेगा। व्यापारिक विस्तार की योजनाएं मूर्त रूप ले सकती हैं। व्यस्तता के बीच साथी के लिए समय न निकालने पर हल्की नाराजगी हो सकती है।



वृषभ

आज आपको दूसरों पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या कोई दोस्त हो सकता है और व : आपकी किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा।



वृश्चिक

वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे। व्यापार में पुराने ग्राहकों से फिर से अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर सार्थक बातचीत होगी।



मिथुन

आप पिछले कुछ समय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं लेकिन आज आप पर सबका ध्यान आएगा ? लाइमलाइट आप पर रहेगी और आप आसानी से इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को साबित कर पायेंगे ?



धनु

सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने से बड़ा लाभ होगा। व्यापारिक वादों को समय पर पूरा करें। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। धन की आवक अच्छी रहेगी।



कर्क

आपकी क्रिएटिविटी रंग लाएगी। किसी बड़े व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। कारोबार है तो नए ग्राहक और नए अवसर मिलने के स्पष्ट संकेत हैं।



मकर

एकाग्रता से काम करने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। पुराने सौंदर्य से आर्थिक लाभ होगा। आपसी विश्वास और भावनात्मक संबंध गहरे होंगे।



सिंह

आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासन कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। व्यापार में नई रणनीति कारगर साबित होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।



कुम्भ

जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन वरिष्ठों का मार्गदर्शन काम आएगा। व्यापार में उधारी देने से बचें। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे।



कन्या

नौकरी में आपके कार्य की प्रशंसा होगी। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से आप कारोबार में आगे रहेंगे। साथी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा।



मीन

कार्यस्थल पर आपकी बारीकी और व्यवस्थित कार्यशैली की तारीफ होगी। नया व्यापारिक सौदा पक्का हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं को प्राथमिकता दें।

बॉलीवुड

मन की बात

आज के दौर में सिनेमा को नॉर्थ और साउथ में बांटकर न देखें : करीना



फिल्मी दुनिया में अब नॉर्थ और साउथ का फर्क धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। एक्टर्स भी अब सिर्फ अपनी-अपनी इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं हैं। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म ‘दायरा’ है, जिसमें बॉलीवुड की करीना कपूर खान के साथ मलयालम सिनेमा के बड़े अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन मारन नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज से पहले करीना कपूर खान, पृथ्वीराज सुकुमारन और डायरेक्टर मेघना गुलजार ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत की। जब करीना और पृथ्वीराज से एक-दूसरे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस पूछा गया, तो दोनों ने सिर्फ अपने को-स्टार की तारीफ नहीं की, बल्कि यह भी बताया कि आज के दौर में सिनेमा को नॉर्थ और साउथ में बांटकर देखने की जरूरत नहीं है। करीना कपूर खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मेघना ने इस फिल्म के लिए दो ऐसे कलाकारों को साथ लाने के बारे में सोचा, जो इससे पहले एक-दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पृथ्वीराज का काम देखा था और उनके बारे में काफी सुना था। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज भी फिल्म का हिस्सा हैं, तो उन्हें लगा कि यह जोड़ी कुछ नया लेकर आएगी। करीना ने आगे कहा, कई बार कुछ लोगों को साथ लाना सिर्फ किस्मत का हिस्सा होता है। उनके मुताबिक, पृथ्वीराज मलयालम सिनेमा से आते हैं और उन्होंने वहां बहुत काम किया है, लेकिन आखिर में दोनों की पहचान एक कलाकार के तौर पर ही है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कलाकारों को इस आधार पर क्यों अलग किया जाए कि वे किस तरह का सिनेमा करते हैं या देश के किस हिस्से से आते हैं। करीना ने साफ शब्दों में कहा कि कलाकारों के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जैसी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर हेरान कर देने वाला परफॉर्म कर रही है। खासतौर पर इसके चौथे हफ्ते की कमाई किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले हफ्ते में 1.08 करोड़ रुपये से शुरुआत करने के बाद, इसने चौथे हफ्ते में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। इन आंकड़ों के साथ ही इस फिल्म ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चलिए यहां इसके 28वें दिन का कलेक्शन जानते हैं। मामूली से बजट में बनी हनुमान अंश ने बड़ी-बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। रिलीज के 28वें दिन तो इसने टॉक्सिक जैसी 500



चौथे हफ्ते बाक्स आफिस पर हनुमान अंश ने तोड़ा कई फिल्मों का रिकॉर्ड

करोड़ी फिल्म को भी मात दे दी।

सैकनल्क के आंकड़ों के मुताबिक हनुमान अंश ने रिलीज के चौथे गुरुवार यानी 28वें दिन 11 करोड़ रुपये की भारी कमाई की। वहीं 27वें दिन की 7।75 करोड़ रुपये की कमाई

बता दें कि हनुमान अंश 1.8 करोड़ रुपये के बजट में बनी हुई बताई जा रही है। वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने अब तक 72.88 करोड़ रुपये (नेट) कमाए हैं। इस तरह, 28 दिनों में फ़िल्म ने 71.08 करोड़ रुपये का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल किया है जो कि 3948.88 फीसदी का धमाकेदार मुनाफा है। इसी के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है।

की तुलना में इसमें 41.94 फीसदी की तेजी देखी गई जो वाकई होश उड़ा देने वाला ट्रेंड है।

इस फिल्म ने अपनी रिलीज के चौथे

हफ्ते में 61 करोड़ रुपये (नेट) कमाए। इसी के साथ इसने अपने तीसरे हफ्ते के 10.4 करोड़ के कलेक्शन के मुकाबले चौथे वीक में 86.54 फीसदी की तेजी दिखाई। अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की 28 दिनों की कुल कमाई 72.88 करोड़ रुपये (नेट) है। जबकि इसका ग्राँस कलेक्शन 86 करोड़ रुपये पहुंच गया है। रिलीज के चौथे वीक में 61 करोड़ रुपये की कमाई करन के साथ ही हनुमान अंश ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में चौथे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। इसने धुरंधर 2 (56 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़कर लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपना कब्जा जमाया है। बता दें कि इस लिस्ट में धुरंधर (115.7 करोड़ रुपये) सबसे ऊपर है।

मलाइका-अरबाज के बेटे अरहान खान करेंगे बॉलीवुड डेब्यू

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे अरहान खान अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। चाहे कोई बॉलीवुड पार्टी हो या इवेंट, अरहान अपने डैशिंग लुक से हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं। अब अरहान अपने पेरेंट्स के नक्शेकदम पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। वो जल्द ही बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाले हैं।

जूम की एक रिपोर्ट के अनुसार, अरहान खान को बॉलीवुड में एक बड़े एक्शन प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च करने की तैयारी है। इस फिल्म को डायरेक्टर अनिरुद्ध अय्यर बना रहे हैं, जो इससे पहले एन एक्शन हीरो का निर्देशन कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अरहान की डेब्यू फिल्म बड़े लेवल पर बनाई जाएगी, जिसमें जबरदस्त एक्शन देखने को

मिलेगा। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और इसकी स्क्रिप्टिंग लगभग पूरी होने वाली है। अरहान खान के लिए एक्टिंग भले ही नई शुरुआत हो, लेकिन वो कैमरे के सामने पहले भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने डंब बिरयानी नाम का पॉडकास्ट किया था, जिसमें उन्होंने देव राययानी और अरुष वर्मा के साथ काम किया। अब पॉडकास्ट के बाद अरहान बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ऐसे में फैंस को उनके

बॉलीवुड डेब्यू का बेसब्री से इंतजार है। अरहान खान के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर



उनके पिता अरबाज खान से पहले भी सवाल किया जा चुका है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अरबाज ने कहा था, अरहान के लिए स्क्रिप्ट मेरे पास से भी आ सकती है और किसी दूसरे फिल्ममेकर की तरफ से भी। आज के समय में कई लोगों की नजर अरहान पर है। अगर मेरे पास उसके लिए कोई अच्छी कहानी आती है, तो मैं उसे फिल्म ऑफर करूंगा। इसके बाद फैसला अरहान का होगा कि वह फिल्म करना चाहता है या नहीं। बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की शादी 12 दिसंबर 1998 को हुई थी। शादी से पहले दोनों ने करीब पांच साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। शादी के बाद दोनों ने बेटे अरहान खान का वेकमल किया।

अजब-गजब

इन गांव के आगे बड़े-बड़े शहर हैं फेल

ये हैं भारत के सबसे अमीर गांव, हर घर में करोड़पति

भारत में कुछ गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ करोड़पति रहते हैं। इन गांवों की चमचमाती सड़कें फॉरेन कंट्री का फील देती हैं। इन गांवों का हर मकान पक्का-सुंदर है। हर घर-गली में अमीरी झलकती है। कुछ गांवों में दर्जनों बैंक भी हैं। आज हम ऐसे ही 5 गांवों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये गांव महाराष्ट्र-गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश में हैं। इस लिस्ट में पहला नाम हिवरे बाजार गांव का जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है। इस गांव की कहानी पूरे देश के लिए उम्मीद है। किसी जमाने में यह गांव पलायन-गरीबी और हताशा का प्रतीक था। आज इसकी पहचान करोड़पति गांव के रूप में होती है। पहले यहां जमीन बंजर थी, कुआं में पानी नहीं था। गांव की 90 फीसदी आबादी गरीब थी। 1989 में यहां पोपट राव बागूजी पवार नाम के शख्स गांव लौटे। उन्होंने गांव की किस्मत पलट दी। उन्होंने पंचसूत्रीय योजना से गांव की तस्वीर बदल दी। आज इस गांव को आदर्श ग्राम, निर्मल ग्राम, वनग्राम का पुरस्कार मिल चुका है। यहां के किसानों की औसत आय? 30,000 महीना है। गांव में 235 परिवारों हैं। इसमें से 60 परिवार लखपति हैं।

इस लिस्ट में दूसरा नाम माधापर गांव का है जो कि गुजरात के कुछ जिले में आता है। यह भुज शहर के पास है। माधापर गांव कम शहर ज्यादा लगता है। आबादी करीब 60 हजार है



लेकिन यहां 16 बैंक हैं। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के रूप में लोगों के पांच हजार करोड़ रुपये जमा हैं। इस गांव की अमीरी की कहानी का राज बहुत दिलचस्प है। दरअसल, अफ्रीका में 1945 में रेलवे लाइन डाली जा रही थी। इसको बिछाने के लिए मजदूर कच्छ से अफ्रीका गए। यहां के लोग अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड गए, वहां काम किया। ये एनआरआई अपनी जिंदगीभर की जमा-पूँजी के साथ इस गांव में लौट आए हैं। गांव के लोगों के ज्यादातर बच्चे विदेश में सेटल हैं।

गुजरात के आणंद का गांव धर्मज भी इस लिस्ट में है। इस गांव के हर घर से एक परिवार विदेश में है। इस गांव में भी 14 बैंक हैं। गांव के विकास में ग्रामीणों ने मिलकर काम किया। इस गांव को गुजरात का पेरिस बोलते हैं। गांव में स्कूल-कॉलेज और अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, वॉटर पार्क, स्वीमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क की सुविधा है। गांव की अपनी एक

आत्मकथा है। गांव का अपना एक एंथम है। गांव का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

इस लिस्ट में गुजरात का एक और गांव पुंसरी है। यह साबरकांठा जिले में आता है। लोकतांत्रिक मूल्यों और पंचायती राज का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। गांव में बिजली-हाईटेक शिक्षा, मिनिरल वॉटर, इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां के पूर्व प्रधान हिमांशु पटेल ने गांव की किस्मत बदली। गुजरात के भुज जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बल्लिया गांव भी स्मार्ट विलेज में आता है। 8000 लोगों के इस छोटे से गाँव की कुल संपत्ति 1200 करोड़ रुपये है।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का मड़ावग (मरोग) गांव एशिया के सबसे अमीर गांवों में गिना जाता है। यह गांव मुख्य रूप से सेब की खेती के लिए फेमस है। यह शिमला के चौपाल में स्थित है। यह क्षेत्र सेब के बागानों और समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। मड़ावग गांव के लोगों ने सेब की उन्नत किस्मों की खेती की। मॉडर्न तकनीकी अपनाई। आज हर घर में करोड़पति किसान हैं। 1954 में गांव के किसान छेनिया राम मेहता ने अपनी आलू की फसल बेचकर कोटखाई में सेब के प्लांट खरीदे। धीरे-धीरे पूरे गांव के किसान सेब की खेती करने लगे।

दुनिया की अनोखी इमारत, जो दूर से देखने में लगती है बिजली के प्लग जैसी

कल्पना कीजिए कि किसी इमारत को बनाने के लिए मजदूर नीचे से ऊपर जाने के बजाय ऊपर से नीचे की तरफ काम कर रहे हों। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुनिया में ऐसी इमारतें वास्तव में मौजूद हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बनी एक मशहूर इमारत इसी अनोखे तरीके से तैयार की गई थी। मैड्रिड के प्लाजा दे कोलोन में खड़ी दो जुड़ाव इमारतों को स्थानीय लोग प्यार से ‘El Enchufe’ यानी ‘The Plug’ कहते हैं। इसकी बनावट देखने पर सच में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बिजली का प्लग आसमान में लटका हुआ हो। इसका ऑफिसियल नाम टोरेस डे कोलोन यानी Columbus Towers है। यह इमारत मैड्रिड की पहचान बन चुकी है। साल 1976 में तैयार हुई यह इमारत शहर के स्काईलाइन का हिस्सा है। हालांकि, इसकी खूबसूरती को लेकर लोगों की राय हमेशा एक जैसी नहीं रही। कुछ लोग इसे मैड्रिड की सबसे बदसूरत इमारतों में से एक तक कहते हैं। इसके ऊपर बना हरे रंग का आर्ट डेको शैली वाला हिस्सा और कॉपर और स्मोल्ड ग्लास से बनी बाहरी दीवारें इसे बाकी इमारतों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। लेकिन इसकी असली खासियत इसका बाहरी डिजाइन नहीं, बल्कि इसे बनाने का तरीका था। आमतौर पर किसी भी ऊंची इमारत का निर्माण जमीन से शुरू होता है। पहले नींव तैयार की जाती है और फिर एक-एक करके मंजिलें ऊपर जाती हैं। लेकिन टोरेस डे कोलोन में तरीका बिल्कुल उल्टा था। सबसे पहले जमीन पर दो मजबूत खंभे बनाए गए। इसके बाद सबसे ऊपर वाली मंजिल तैयार की गई और उसे स्टील की मजबूत केबलों की मदद से ऊपर लटका दिया गया। फिर उसके नीचे अगली मंजिल बनाई गई और उसे भी ऊपर की ओर लगाया गया। इसी तरह धीरे-धीरे बाकी मंजिलें भी तैयार होती गईं। यानी इमारत का निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ होता गया। हालांकि, इमारत के निचले हिस्से की कुछ मंजिलों और बेसमेंट का निर्माण सामान्य तरीके यानी नीचे से ऊपर की तरफ किया गया था। टोरेस डे कोलोन की सबसे खास पहचान इसका ऊपरी हिस्सा है। इमारत के ऊपर मौजूद संरचना और दो लंबे केंद्रीय खंभों का संयोजन इसे देखने में एक विशाल इलेक्ट्रिक प्लग जैसा बनाता है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों ने इसे ‘प्लग’, नाम दे दिया गया। बाद में इसके ऊपरी हिस्से में जो प्लग जैसा ढांचा दिखाई देता है, उसने इसकी पहचान को और मजबूत कर दिया। ऊपर से नीचे की तरफ इमारत बनाना कोई आम तरीका नहीं है, लेकिन टोरेस डे कोलोन दुनिया की अकेली ऐसी इमारत नहीं है। आयरलैंड के डबलिन में Central Bank of Ireland और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में Standard Bank Centre भी इसी तरीके से बनाए गए थे। पोलैंड में भी ऐसी इमारतें हैं।



एसआईआर पर महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान

» महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं: क्लाइड क्रैस्टो

4पीएम न्यूज नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेसिव रिवीजन/एसआईआर) को लेकर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी (शरद पवार गुट) के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने दावा किया कि राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जो कुल वोटर्स का करीब 21 फीसदी है। वहीं शिवसेना (उद्धव गुट) के एमएलसी अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि बंगाल में भी 98 लाख लोगों के साथ यही तरीका अपनाया गया था, भाजपा हर राज्य में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनावी रणनीति के तहत कर रही है।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एसआईआर का मामला देखिए। महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। अब, जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, तो चुनाव

विमान हादसे में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुयी

एनसीपी (शरद पवार गुट) के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा, हमारे अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं रहे। हादसे में जो कुछ भी हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई, भारतीय जनता पार्टी इस पर जिस तरह की राजनीति कर रही है, वह गलत है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाजपा इस मामले पर राजनीति कर रही है? क्योंकि, आज भी हादसे से संबंधित कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। भाजपा सरकार में है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी बस यही मांग है कि जो हुआ उसकी एफआईआर रजिस्टर हो और सच, चाहे जो भी हो सामने आए।

आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले लिस्ट में 40 लाख नाम रजिस्टर किए थे। अब, उन्होंने 2 करोड़ नाम हटा दिए हैं। यह कैसे हुआ? यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि 21 फीसदी नाम हटा दिए गए हैं। 9 करोड़ नाम लिस्ट में थे, अब सिर्फ 7-7.5 करोड़ नाम हैं। क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि जेन-जी इस देश का भविष्य है। आपने

देखा कि उन्होंने जंतर-मंतर पर कैसे प्रोटेस्ट किया और धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। जिस तरह से वे प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी मांगें रख रहे थे, उससे पता चलता है कि जेन-जी ही भविष्य है।

अगर



भाजपा अपने फायदे के लिए कर रही एसआईआर का इस्तेमाल : अंबादास

एसआईआर को लेकर शिवसेना (उद्धव गुट) एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा, मैं आपको बता दूँ, बंगाल में 98 लाख लोगों के लिए यही तरीका अपनाया गया था। मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। अगर उन 98 लाख लोगों को नहीं हटाया गया होता, तो शायद ममता बनर्जी के लिए चुनाव का नतीजा अलग हो सकता था। इसी तरह, हर राज्य में, भारतीय जनता पार्टी इस प्रोसेस का इस्तेमाल पूरी तरह से अपने राजनीतिक फायदे और अपनी चुनावी रणनीति के तहत कर रही है। अंबादास दानवे ने आगे कहा कि हमने आज यहां विधानसभा क्षेत्रों से बीएलए के प्रतिनिधियों को बुलाया था। उद्धव दाक्रे जी ने सभी बीएलए से बातचीत की। मेरा मानना है कि इसका मतलब यह था कि सभी को बीएलए का महत्व समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे संगठन में आम लोग काम करते हैं। मुंबई का माहौल अलग है, जबकि ग्रामीण इलाकों का माहौल अलग है।

अखिलेश यादव जेन-जी के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई

» यह मिशन भारत के लिए अपना पहला डेडिकेटेड इमेजिंग सैटेलाइट हासिल करने जैसा : राज्यपाल

4पीएम न्यूज नेटवर्क



अमरावती। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने जीएसएलवी-एफ17 के सफल लॉन्च पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जीएसएलवी-एफ17 रॉकेट के जरिए अपने सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ईओएस-05, को सफलतापूर्वक लॉन्च करने और उसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की। राज्यपाल ने कहा कि यह मिशन भारत के लिए अपना पहला डेडिकेटेड इमेजिंग सैटेलाइट हासिल करने जैसा है, जो लगातार निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इससे इसरो की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जीएसएलवी-एफ17 के सफल लॉन्च और ईओएस-05 को उसकी तय कक्षा (ऑर्बिट) में सही ढंग से स्थापित करने के लिए इसरो को बधाई। यह शानदार उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं की ताकत और हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पण को दिखाती है। भविष्य में और भी कई उपलब्धियां हासिल करने के लिए इसरो की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इस लॉन्च को पृथ्वी से सितारों तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया मील का पत्थर बताया।

बिग-बॉस-20 में काउबॉय लुक में नजर आए सलमान खान

» पैपराजी को लगाई फटकार 4पीएम न्यूज नेटवर्क

मुंबई। अभिनेता सलमान खान लोकप्रिय रियलिटी शो बिग-बॉस-20 में होस्ट के तौर पर वापसी के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अभिनेता ने शो की शूटिंग शुरू दी है। इस दौरान अभिनेता पैपराजी से थोड़ा नाराज नजर आए। शूटिंग के लिए अभिनेता ने काउबॉय लुक अपनाया हुआ था। शो में जाने से पहले उन्होंने पैपराजी को पोज दिए और स्टेज से दूरी बनाने का निर्देश भी दिया। हालांकि उन्हें किस बात ने उकसाया यह अभी साफ नहीं है। सेट पर सलमान खान काउबॉय लुक में नजर आए। उन्होंने गहरे भूरे रंग की लेदर काउबॉय हैट, नेवी ब्लू टी-शर्ट और ऑलिव ग्रीन वेस्ट पहनी थी।

इस लुक को उन्होंने डेनिम, सिल्वर बेल्ट और अपने ट्रेडमार्क फिरोजी ब्रेसलेट के साथ पूरा किया। सोलो पोज देने के बाद अभिनेता ने पैपराजी के कहने पर उनके साथ भी फोटो खिंचवाई। हालांकि अभिनेता पैपराजी पर भड़कते हुए भी नजर आए। उन्होंने यह कहते हुए सुना गया, यह मेरा काम नहीं है और मुझे कैमरे के आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। बिग बॉस के नए सीजन की बात करें तो, यह हिंदी रियलिटी शो का 20वां एडिशन है, जिसमें सलमान होस्ट के तौर पर वापस आ रहे हैं। सीजन का प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता, सलमान 2010 में अमिताभ बच्चन की जगह सीजन 4 के होस्ट बनने के बाद से ही बिग बॉस का चेहरा रहे हैं। लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस के मुख्य और सबसे लंबे समय तक रहने वाले होस्ट सलमान खान हैं, जो आगामी सीजन बिग बॉस 20 को भी होस्ट कर रहे हैं। सलमान खान लगातार इस शो का मुख्य चेहरा बने हुए हैं, हालांकि बीच में संजय दत्त (सीजन 5), फराह खान (विशेषांक/स्पिन-ऑफ) ने भी साथ या आंशिक रूप से होस्ट किया है। बिग बॉस में कई प्रतियोगी (कंटेस्टेंट) एक विशेष रूप से बनाए गए घर में बिना किसी बाहरी संपर्क के एक साथ रहते हैं।

तमिलनाडू में तेजी से बढ़ रहे डेंगू प्रकरण

» डेंगू के 13,573 मामले सामने आए और नौ लोगों की हुई मौत 4पीएम न्यूज नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु में पिछले साल की तुलना में डेंगू और स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे देखते हुए डॉक्टर अधिक सावधानी बरतने और बचाव के कड़े उपाय करने की सलाह दे रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जनवरी से 30 अगस्त 2026 के बीच राज्य भर में डेंगू के 13,573 मामले सामने आए और नौ लोगों की मौत हुई हालांकि मौत की दर अभी भी काफी कम है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स जुलाई और अगस्त के दौरान संक्रमण के मामलों में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं।

जनवरी में डेंगू के 1,722, फरवरी में 1,322, मार्च में 1,228, अप्रैल में 1,201 और



मई में 1,062 मामले सामने आए। जून में मामलों में फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई, जब संक्रमण के 1,384 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद जुलाई में 2,339 और अगस्त में 3,315 मामले सामने आए। पिछले साल की तुलना में यह बढ़ोतरी काफी अहम है। पिछले साल जुलाई में डेंगू के 1,880 मामले थे जो इस साल जुलाई में बढ़कर 2,339 हो गए, जबकि अगस्त में संक्रमण के मामले 1,832 से बढ़कर 3,315 हो गए। चेन्नई में सबसे ज्यादा मामले

स्वाइन फ्लू में भी हुई बढ़ोतरी

स्वाइन फ्लू के संक्रमण में भी बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु में इस साल 1,500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण के मामलों के लिहाज से यह देश के राज्यों में दूसरे स्थान पर है। हेल्थ डेटा से भी पता चलता है कि हाल के वर्षों की तुलना में खासकर जून, जुलाई और अगस्त के दौरान मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में हुई बढ़ोतरी खास तौर पर ध्यान देने लायक है, पिछले साल इसी महीने में स्वाइन फ्लू के सिर्फ 46 मामले थे, जो इस साल बढ़कर 645 हो गए हैं।

सामने आए हैं। जनवरी से अगस्त के बीच राज्य में कुल 13,573 संक्रमण के मामलों में से 2,584 मामले यहीं दर्ज किए गए। इसके बाद कोयंबटूर में 1,999 मामले सामने आए। मामलों में इस बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि चेन्नई सहित तमिलनाडु में मानसून का समय अभी आना बाकी है। पिछले साल तमिलनाडु में डेंगू के 25,533 मामले दर्ज किए गए थे। यह संख्या 2022 और 2024 के बीच देखे गए ज्यादा मामलों की तुलना में काफी कम थी।

गोल्ड में गिरावट जारी सिल्वर भी आठ हजार रुपए से हुई सस्ती

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। सोने और चांदी में इस हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिली जिससे दोनों कीमती धातुओं का दाम क्रमशः 4,000 रुपए और 8,000 रुपए से अधिक घट गया। आईबीजेए के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 4,694 रुपए कम होकर 1,54,884 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पहले यह 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

22 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,41,874 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,46,173 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,16,163 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,19,684 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस हफ्ते 24 कैरेट सोने में सबसे न्यूनतम दाम 2 सितंबर को शाम के सत्र में 1,51,184 रुपए प्रति 10 ग्राम देखा गया।

यूएस ओपन में हारी सेरेना-विनस विलियम्स की जोड़ी

» चैन और जॉइंट ने शुरुआत में ही बना लिया था नियंत्रण 4पीएम न्यूज नेटवर्क

न्यूयॉर्क। सेरेना विलियम्स और विनस विलियम्स को यूएस ओपन डबल्स में हार का सामना करना पड़ा है। आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में विलियम्स बहनों को चैन हाओ-चिंग और माया जॉइंट की जोड़ी ने निर्णायक सुपर टाईब्रेक में जीत हासिल की। शुरुवार शाम को तीन घंटे तक चले मैच में, चैन और जॉइंट ने 14 बार की ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन को 6-3, 6-7 (8), 7-6 [7] से हराकर दूसरे राउंड में जगह बनाई। इस परिणाम ने विलियम्स बहनों को टूर्नामेंट में दमदार वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खचाखच भरे ऐश स्टेडियम में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जो बार-बार दोनों टीमों के बीच घूमता

रहा और आखिर में नतीजा तय करने के लिए सुपर टाईब्रेक की जरूरत पड़ी।

चैन और जॉइंट ने शुरुआत में ही नियंत्रण बना लिया और पहला सेट 6-3 से जीत लिया। लेकिन, विलियम्स बहनों ने दूसरे सेट में नए जोश के साथ जवाब दिया और अपनी अपोनेंट्स को सर्व पर कोई मौका नहीं दिया। सेट टाईब्रेक तक गया, जिसमें कोई भी जोड़ी 12 गेम तक बराबरी नहीं कर पाई। सेरेना और विनस ने ब्रेकर में 5-3 से

बढ़त बना ली, जब सेरेना ने बैकहैंड वॉली विनर बनाया, लेकिन चैन और जॉइंट टचिंग डिस्टेंस के पास ही रहे। चैन के नेट पर विनर ने मुकाबला जिंदा रखा, इससे पहले कि विलियम्स बहनों ने एक और सेट पॉइंट हासिल किया। फिर जॉइंट ने एक अनरिटर्नड सर्व करके स्कोर 6-5 कर दिया, लेकिन अगले मौके पर सेरेना ने डबल फॉल्ट कर दिया। विलियम्स बहनों की कई महंगी गलतियों ने उनके विरोधियों को वापसी करने का मौका दिया। नेट में लगातार शॉट लगाने से अंतर कम हुआ, इससे पहले कि विनस ने 6-3 पर डबल फॉल्ट किया। चैन और जॉइंट ने मौके का फायदा उठाया और लगातार छह पॉइंट



हार से पहले मजबूत दिख रही थी बहनों

विलियम्स बहनों ने आखिरकार अपना पांचवां सेट पॉइंट तब बदला जब जॉइंट ने फोरहैंड बेसलाइन के पार भेजा, जिससे मुकाबला निर्णायक सेट में चला गया। निर्णायक सेट की शुरुआत में विनस और सेरेना का पलड़ा मजबूत लग रहा था, लेकिन चैन और जॉइंट ने जल्दी ही 4-1 से आगे बढ़कर पासा पलट दिया। विलियम्स बहनों ने लगातार तीन गेम जीतकर सेट बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने बाकी सेट में अपनी सर्विस बनाए रखी, जिससे मैच सुपर टाईब्रेक में चला गया। सेरेना और विनस ने शानदार शुरुआत की, 5-0 की बढ़त बना ली और यादगार वापसी वाली जीत के बहुत करीब पहुंच गईं। लेकिन फिनिश पूरी तरह से चैन और जॉइंट के नाम रहा।

बनाए। फिर चैन ने मैच पॉइंट पर वॉली विनर मारकर टूर्नामेंट की सबसे रोमांचक जीतों में से एक पूरी की और विलियम्स बहनों की न्यूयॉर्क डबल्स कॉम्पिटिशन में वापसी खत्म कर दी।

कलेक्ट्रेट की मस्जिद पर चला बुलडोजर, सहारनपुर में तनाव

» जिला जज के फैसले के बाद प्रशासन का एक्शन, पांचों गेट सील कैराना सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट

4पीएम न्यूज नेटवर्क

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार सुबह प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। जिला जज की अदालत द्वारा दो सितंबर को प्रशासन के पक्ष में फैसला बरकरार रखे जाने के बाद शनिवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी और डंपर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचाए गए और मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के सभी पांचों गेट सील कर दिए गए हैं और बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह रोक दी गई है। मौके पर पुलिस के साथ आरएफ को भी तैनात किया गया है।

प्रशासन की कार्रवाई के बीच इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। इसी बीच कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को हाउस अरेस्ट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। प्रशासन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही सहारनपुर का यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई अदालत के आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि विवादित निर्माण सरकारी जमीन पर था और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। यही वजह है कि प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था



लंबे समय से चल रहा था विवाद

मामले की पृष्ठभूमि में कलेक्ट्रेट परिसर की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद है। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। इसी आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामला अपील तक पहुंचा, लेकिन प्रशासन के मुताबिक मस्जिद कमेटी की पहली अपील खारिज हो गई। इसके बाद दो सितंबर को जिला जज की अदालत ने भी प्रशासन के पक्ष में पहले के फैसले को बरकरार रखा।

कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास सुरक्षा का घेरा

अदालती फैसले के बाद प्रशासन ने आज कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके बाद जेसीबी और डंपर मौके पर पहुंचाए गए। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में मस्जिद के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। कलेक्ट्रेट के पांचों गेट बंद किए जाने के बाद पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में एक मस्जिद थी, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध पाया गया था। उन्होंने बताया कि इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी फर्स्ट अपील में गई थी, लेकिन उसकी अपील खारिज हो गई। इसके बाद अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

मस्जिदों को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण का अभियान तत्काल रोके सरकार: मायावती

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में मस्जिदों समेत अन्य धार्मिक स्थलों को अवैध बताकर ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से इसे तत्काल रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार की जिम्मेदारी सभी धर्मों के मानने वालों तथा उनके धार्मिक स्थलों का समान रूप से सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



को लेकर विशेष सतर्कता बरती है। वहीं, दूसरी तरफ मस्जिद से जुड़ा मामला होने के कारण प्रशासन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या तनाव की आशंका को लेकर बेहद सावधानी बरत रहा है। कलेक्ट्रेट के सभी प्रवेश द्वार बंद किए

जाने और आरएफ को तैनाती को इसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा न हों और किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो।

इंग तस्करी मामले में मुंबई से दो विदेशी नागरिकों गिरफ्तार

4पीएम न्यूज नेटवर्क

इंदौर। भारत में बिजनेस और ट्रेवलिंग वीजा पर युगांडा और नाइजीरिया से आए लोगों द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी मामले में इंदौर पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है। पूर्व में पकड़ी गई नाइजीरियन महिला से पूछताछ के आधार पर इंदौर पुलिस ने मुंबई के नाला सोपारा से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इंदौर डीसीपी नरेंद्र रावत के मुताबिक, चंदन नगर पुलिस ने 30 अगस्त को नाइजीरिया की रहने वाली महिला इम्यूनल जॉय को 58 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। इम्यूनल से पूछताछ और उसके मोबाइल फोन की जांच के बाद में पुलिस मुंबई के नाला सोपारा पहुंची। यहां मादक पदार्थ के साथ पकड़ी गई महिला को तस्करी में मदद करने वाली युगांडा की महिला नाकिजवे कावुमा और नाइजीरियन पुरुष नाकायजावे कावूमा को गिरफ्तार किया।

दिल्ली में दो महिला पत्रकारों से मारपीट और बर्बरता पर गरजा कानपुर में आईरा प्रेस क्लब



» पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, कार्रवाई होने तक आईरा प्रेस क्लब की आवाज नहीं थमेगी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

कानपुर। दिल्ली के साकेत क्षेत्र में 4 PM न्यूज नेटवर्क से जुड़ी दो महिला पत्रकारों के साथ कवरेज के दौरान कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पत्रकारों के साथ पुलिस बर्बरता के विरोध में आज कानपुर जिले में ऑल इंडियन रिपोर्ट्स एसोसिएशन (आईरा प्रेस क्लब) ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। संगठन ने शुक्रवार को कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और कथित दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन प्रक्रिया का नेतृत्व जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरज वर्मा और जिला वरिष्ठ मंत्री तल्हा हाशमी ने किया। इस दौरान आईरा प्रेस क्लब ने साफ शब्दों में कहा कि पत्रकार चाहे महिला हो या पुरुष, उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरज वर्मा ने मामले को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला पत्रकारों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल किए, जिसके बाद उनके साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर मारपीट और बर्बर व्यवहार किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पत्रकारों द्वारा सवाल पूछना ही अपराध बन जाएगा तो लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता का क्या अर्थ रह जाएगा। सूरज वर्मा ने शिकायत के बावजूद कार्रवाई में कथित देरी पर भी सवाल खड़े किए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

वहीं जिला वरिष्ठ मंत्री तल्हा हाशमी ने दो टूक कहा कि यह मामला किसी पत्रकार के महिला या पुरुष होने से आगे बढ़कर देश के चौथे स्तंभ पर कथित हमले का है उन्होंने कहा कि आईरा प्रेस क्लब 4PM

आईरा प्रेस क्लब ने साफ कर दिया, अब चुप्पी नहीं

तल्हा हाशमी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर आईरा प्रेस क्लब अब पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आईरा प्रेस क्लब संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा और जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर धरना-प्रदर्शन भी करेगा।

15 दिन का अल्टीमेटम, फिर दिल्ली कूच की चेतावनी

ज्ञापन सौंपने के बाद सूरज वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईरा प्रेस क्लब ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि ज्ञापन को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा और संगठन की मांगों से वहां के अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा आईरा प्रेस क्लब ने 15 दिन का समय देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि में साकेत प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा और धरना-प्रदर्शन एवं आंदोलन करेगा।

‘कार्रवाई होने तक नहीं थमेंगे’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूरज वर्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पत्रकारों पर हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद गंभीर विषय है। संगठन का कहना है कि पत्रकारों को कवरेज के दौरान भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए और किसी भी कथित उत्पीड़न की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आईरा प्रेस क्लब ने यह भी स्पष्ट किया कि वह 4PM की दोनों महिला पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ा है और न्याय की मांग को लेकर अखिरी दम तक आवाज उठा रहेगा।

देश में सवाल पूछना अपराध

संगठन का संदेश साफ है—पत्रकार पर कथित हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता के अधिकार पर चोट है। कार्रवाई होगी तो स्वागत, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो आईरा प्रेस क्लब आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगा।

न्यूज नेटवर्क की उन महिला पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिनके साथ कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार हुआ। संगठन ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाए।

नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन काटे जाने का मामला गरमाया, संडे को महापंचायत

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नोएडा। नोएडा के डूब क्षेत्र में विकसित की गई अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन काटे जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद विद्युत विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए इन कॉलोनियों में 13 हजार से अधिक बिजली कनेक्शन काटे जाने की बात

सामने आई है। बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद यहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा के डूब क्षेत्र में लंबे समय से बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां विकसित होती रही हैं। इन कॉलोनियों में हजारों परिवार रह रहे हैं।